

अनुच्छेद 142

प्रलिस के लयि:

राष्ट्रपतकी कषमादान शक्ति, अनुच्छेद 72, राष्ट्रपति, राज्यपाल

मेन्स के लयि:

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पूरण न्याय अपनाने में चुनौतयिँ (अनुच्छेद 142), अनुच्छेद 162

चर्चा में क्यँ?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने संवधान के अनुच्छेद 142 के तहत पूरण न्याय प्रदान करने की अपनी असाधारण शक्तयिँ का प्रयोग कयि और [पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्या मामले](#) में एजी पेरारविलन को ररिा करने का आदेश दयि है।

- न्यायालय ने संघवाद की रक्षा करते हुए कहा क हत्या के मामलों में दोषयिँ द्वारा कयि गए [अनुच्छेद 161](#) के तहत कषमा की याचिका के मामले में राज्यों के पास राज्यपाल को सहायता और सलाह देने की शक्ति है।
- **अनुच्छेद 161** में यह प्रावधान है क कसि भी मामले से संबंधति कसि भी कानून के खलिाफ कसि भी अपराध के लयि राज्य द्वारा दयि गए दंड के संबंध में **राज्यपाल** के पास दंड को नलिंबति करने, दंड की अवधि को कम करने, दंड के स्वरूप में परिवर्तन करने की शक्ति होगी।

सर्वोच्च न्यायालय का नरिणय:

- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा क तमलिनाडु मंत्रपरिषद द्वारा वर्ष 2018 में राज्यपाल को दी गई कषमादान की सलाह संवधान के [अनुच्छेद 161](#) (राज्यपाल की कषमादान की शक्ति) के अंतरगत राज्यपाल के लयि बाध्यकारी है।
- कषमा याचिका पर नरिणय लेने की राज्यपाल की अनच्छिा ने न्यायालय को पेरारविलन के साथ न्याय करने के लयि **अनुच्छेद 142** के तहत अपनी संवधानिक शक्तयिँ को नयिोजति करने के लयि बाध्य कयि।
- पेरारविलन को ररिा करने के लयि सर्वोच्च न्यायालय ने संवधान के **अनुच्छेद 142** का इस्तेमाल कयि जो न्यायालय को पूरण न्याय प्रदान करने हेतु असाधारण शक्तयिँ प्रदान करता है।
- न्यायालय ने केंद्र के इस तरक को खारजि कर दयि क विशिष रूप से केवल राष्ट्रपति के पास **भारतीय दंड संहति** की धारा 302 (हत्या) के तहत कसि मामले में कषमादान प्रदान करने की शक्ति है, सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा क यह वविाद अनुच्छेद 161 को एक "मृत्यु पत्र" के समान बना देगा और एक असाधारण स्थति पैदा कर देगा जो राज्यपालों द्वारा पछिले 70 वर्षों से हत्या के मामलों में दी गई कषमा को अमान्य कर देगा।

अनुच्छेद 142:

- **परभाषा:** अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को वविकाधीन शक्ति प्रदान करता है क्यँक इसमें कहा गया है क सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार कषेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसी डकिरी पारति कर सकता है या ऐसा आदेश दे सकता है जो उसके समकष लंबति कसि भी मामले या मामलों में पूरण न्याय करने के लयि आवश्यक हो।
- **रचनात्मक अनुप्रयोग:** अनुच्छेद 142 के वकिस के शुरुआती वर्षों में आमजनता और वकीलों दोनों ने समाज के वभिन्न वंचति वर्गों को पूरण न्याय दलिाने या पर्यावरण की रक्षा करने के परयासों के लयि सर्वोच्च न्यायालय की सराहना की।
 - इसी अनुच्छेद के अंतरगत ताजमहल की सफाई का नरिणय और कई वचिराधीन केंदरिों को न्याय प्रदान कयि गया है।
- भोपाल गैस त्रासदी के पीड़तिों से संबंधति यूनयिन कारबाइड मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने खुद को संसद या राज्यों की वधिानसभाओं द्वारा बनाए गए कानूनों से ऊपर रखते हुए कहा क न्याय को पूरा करने के लयि वह संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की भी अवहेलना कर सकता है।
 - हालाँक सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ' मामले में कहा गया क अनुच्छेद 142 का उपयोग मौजूदा कानून को प्रतसिथापति करने के लयि नहीं, बल्क एक वकिल्प के तौर पर कयि जा सकता है।
- **न्यायक अतरिक के मामले:** हाल के वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय ने कई ऐसे नरिणय दयि हैं जनिमें यह अनुच्छेद उन कषेत्रों में भी हस्तकषेप करता है जनिहें न्यायालय द्वारा **शक्तयिँ के पृथक्करण के सिधांत** के माध्यम से भुला दयि गया है। उल्लेखनीय है क **शक्तयिँ के पृथक्करण** का सिधांत

भारतीय संविधान के मूल ढाँचे का एक भाग है।

- **राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध:** केंद्र सरकार की अधिसूचना में जहाँ केवल राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे शराब की दुकानों पर प्रतिबंध लगाया गया था, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 142 को लागू करते हुए 500 मीटर की दूरी तक प्रतिबंध लगा दिया है।
- इसके अतिरिक्त और किसी भी राज्य सरकार द्वारा इसी तरह की अधिसूचना के अभाव में न्यायालय ने प्रतिबंध को राज्य राजमार्गों पर भी बढ़ा दिया।
- इस तरह के फैसलों ने अनुच्छेद 142 को लागू करने के लिये न्यायालय के वविक के बारे में अनिश्चिता पैदा कर दी है, जहाँ व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की भी अनदेखी की जा रही है।

आगे की राह

- सर्वोच्च न्यायालय को इस बात पर आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है कि क्या अनुच्छेद 142 का शक्ति के स्वतंत्र स्रोत के रूप में उपयोग सख्त दशा-नरिदेशों द्वारा नरितरति किया जाना चाहिये।
- एक अन्य विकल्प यह है कि अनुच्छेद 142 को लागू करने वाले सभी मामलों को कम-से-कम पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेजा जाना चाहिये ताकि वविक का यह प्रयोग लोगों के जीवन पर इस तरह के दूरगामी प्रभाव वाले मामलों पर काम कर रहे पाँच स्वतंत्र न्यायिक दमियों का परिणाम मलि सके।
- उन सभी मामलों में जहाँ अदालत अनुच्छेद 142 को लागू करती है, सरकार को इसकी तारीख से छह महीने या उससे अधिक की अवधि के बाद लाभकारी और साथ ही फैसले के नकारात्मक प्रभावों का अध्ययन करने के लिये एक श्वेतपत्र लाना चाहिये।

राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति क्या है?

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 की न्यायिक शक्ति के तहत अपराध के लिये दोषी करार दिये गए व्यक्तियों को राष्ट्रपति क्षमा अर्थात् दंडादेश का नलिबन, प्राणदंड स्थगन, राहत और माफी प्रदान कर सकता है। इन शब्दों का अर्थ इस प्रकार है:
 - **लघुकरण (Commutation)**- सज़ा की प्रकृति को बदलना जैसे मृत्युदंड को कठोर कारावास में बदलना।
 - **परहार (Remission)**- सज़ा की अवधि को बदलना जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदलना।
 - **वसिम (Respite)**- वशिष परिस्थितियों की वजह से सज़ा को कम करना जैसे शारीरिक अपंगता या महिलाओं की गर्भावस्था के कारण।
 - **प्रवलिबन (Reprieve)**- किसी दंड को कुछ समय के लिये टालने की प्रक्रिया जैसे फौसी को कुछ समय के लिये टालना।
 - **क्षमा (Pardon)**- पूर्णतः माफ़ कर देना, इसका तकनीकी मतलब यह है कि अपराध कभी हुआ ही नहीं।

वगित वर्ष के प्रश्न:

प्रश्न. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के अनुसार, सामान्य कानूनों में नहिनि नषिध या सीमाएं या प्रावधान संविधानिक शक्तियों पर प्रतिबंध या सीमाओं के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं। नमिनलिखिति में से इसका क्या अर्थ हो सकता है? (2019)

- (A) भारत नरिवाचन आयोग द्वारा अपने कर्तव्यों का नरिवाहन करते हुए लिये गए नरिण्यों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
- (B) भारत का सर्वोच्च न्यायालय संसद द्वारा बनाए गए कानूनों द्वारा अपनी शक्तियों के प्रयोग के लिये बाध्य नहीं है।
- (C) देश में गंभीर वतितीय संकट की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति मंत्रिमंडल से परामर्श किये बिना वतितीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है।
- (D) संघ वधिानमंडल की सहमति के बिना राज्य वधिानमंडल कुछ मामलों पर कानून नहीं बना सकते हैं।

उत्तर: B

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 (1) के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारति कर सकता है या ऐसा आदेश दे सकता है जो उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले या मामलों में पूर्ण न्याय करने के लिये आवश्यक हो या इस प्रकार किये गए आदेश भारत के पूरे क्षेत्र में ऐसी रीति से लागू करने योग्य होंगे जो संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके तहत नरिधारति की जा सकती है और जब तक इस संबंध में प्रावधान नहीं किया जाता है, तब तक राष्ट्रपति आदेश द्वारा नरिधारति कर सकता है।
- इस प्रकार अनुच्छेद 142 संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को पहले से दी गई शक्तियों का पूरक है ताकि यह सुनिश्चति किया जा सके कि न्याय किया गया है और न्यायालय अधिकार क्षेत्र या कानूनी प्रधिकार की कमी के कारण बाधति नहीं होता है।

अतः विकल्प (B) सही है

स्रोत: द हट्टी

